



इंडिगो एयरलाइंस संकट — DGCA ने CEO को तलब किया



नई दिल्ली: 12 दिसंबर 2025 को DGCA (नागरिक उड्डयन महानियंत्रण) ने इंडिगो एयरलाइंस के CEO पीटर एल्बर्स को हालिया उड़ान रद्दीकरण और क्रू शेड्यूलिंग की समस्याओं पर विस्तृत जवाब देने के लिए तलब किया। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली, बंगलुरु, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों से सैकड़ों उड़ानें रद्द हुईं, जिससे यात्रियों को लंबी दूरी और असुविधा का सामना करना पड़ा। DGCA ने एयरलाइन के संचालन की कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। इंडिगो ने बताया कि अधिकांश रूट अब सामान्य हो रहे हैं, लेकिन यात्रियों पर असर अभी भी बना हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संकट पायलट और चालक दल की कमी से उत्पन्न हुआ है।

NEW DELHI | NDA सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया

पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग पर NDA सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया

नई दिल्ली |

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2025 को अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सांसदों के लिए विशेष डिनर (रात्रिभोज) का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गठबंधन के साथी सांसदों के बीच आपसी संवाद, एकता और रणनीति पर चर्चा को बढ़ावा देना बताया जा रहा है।

भाजपा और NDA के कई वरिष्ठ नेताओं व सांसदों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सभी सांसदों को समूहों में बसों के माध्यम से पीएम आवास तक पहुँचाया गया, ताकि भीड़ नियंत्रण और सुव्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित हो सके।



डिनर की मेज़बानी के दौरान लगभग 54 टेबलों पर सर्व किए गए लजीज़ व्यंजन थे और हर टेबल पर सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्री भी सम्मिलित रहे।

प्रधानमंत्री मोदी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि यह अवसर “एनडीए परिवार की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो सुशासन, राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय

आकांक्षाओं के प्रति समर्पित है।” उन्होंने कहा कि गठबंधन मिलकर देश की विकास यात्रा को और मजबूत करेगा। एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री का आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि यह बैठक बिहार विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बाद विशेष महत्व रखती है।

डिनर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अभिनेत्री-राजनीतिज्ञ कंगना रनौत सहित अन्य राजनीतिक हस्तियों की भी मौजूदगी रही। यह आयोजन संसद के शीतकालीन सत्र के बीच हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य सांसदों के बीच सामंजस्य और आगामी नीति एजेंडों पर अनौपचारिक चर्चा को प्रोत्साहित करना बताया गया।

विश्लेषकों के अनुसार, इस तरह के कार्यक्रम गठबंधन के भीतर सकारात्मक ऊर्जा और साझा लक्ष्यों को सुदृढ़ करने में मदद करते हैं, खासकर चुनावी जीत के बाद की रणनीति को लेकर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए। इस डिनर ने NDA के भीतर नेतृत्व और सहयोग का सकारात्मक संदेश दिया।



राहुल गांधी पर कौसर की टिप्पणी

पार्ट-टाइम पॉलिटिशियन और राहुल गांधी पर मुस्लिम महिला नेता की टिप्पणी

नई दिल्ली: दिल्ली स्टेट हज कमिटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरो और उनके राजनीतिक रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पार्ट-टाइम पॉलिटिशियन हैं और विपक्ष के नेता होते हुए जनता के मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं है। कौसर जहां ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सवाल तो उठाते हैं, लेकिन जब सरकार जवाब देती है तो सदन छोड़कर चले जाते

हैं। इसके अलावा, उनका कहना था कि राहुल गांधी को गोपनीय विदेश यात्राओं का शौक है, जिससे कांग्रेस के ही नेता और कार्यकर्ता परेशान हैं।

कौसर जहां ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जनता को भ्रमित कर रहे हैं और हाल ही में चुसपैठ के मुद्दे पर अमित शाह के भाषण के दौरान वे सदन छोड़कर चले गए। उनका दावा है कि यही कारण है कि जनता ने राहुल गांधी को गंभीरता से लेना

बंद कर दिया है और उनकी पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार-बार ईवीएम और एसआईआर को दोष देते हैं।

कौसर जहां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों का समर्थन करते हुए कहा कि जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है, जबकि राहुल गांधी और उनकी पार्टी इससे बेपरवाह नजर आ रहे हैं।

महाराष्ट्र के 21 हज़ार हज यात्रेकरू अब नहीं होंगे भीड़ में गुम, मनगट पर पहनाई जाएंगी स्मार्ट वॉच

छत्रपति संभाजीनगर | आगामी हज यात्रा के लिए महाराष्ट्र से जाने वाले लगभग 21,000 यात्रेकरूओं की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए इस वर्ष एक महत्वपूर्ण तकनीकी पहल की जा रही है। हज कमिटी ने घोषणा की है कि सभी यात्रेकरूओं के हाथों में विशेष स्मार्ट वॉच पहनाई जाएगी, जिससे वे भीड़भाड़ में खोने या रास्ता भटकने जैसी समस्या से बच सकेंगे।



हर साल मक्का और मदीना में लाखों श्रद्धालु एक साथ इकट्ठे होते हैं। ऐसे वातावरण में यात्रियों को खो जाने की घटनाएँ आम होती हैं। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए हज कमिटी ने इस बार सुरक्षित ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। नई स्मार्ट वॉच में जीपीएस

ट्रैकिंग, लोकेशन शेयरिंग, और आपातकालीन सहायता बटन जैसी सुविधाएँ शामिल होंगी। किसी यात्री को परेशानी होने पर वह सिर्फ एक बटन दबाकर मदद का संकेत भेज सकेगा, जिससे सहायता दल तुरंत उसकी लोकेशन तक पहुँच पाएगा।

हज कमिटी के अनुसार, स्मार्ट वॉच का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के स्थान पर लगातार नज़र रखना, आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुँचाना और भीड़ में एक-दूसरे

से बिछड़ने की समस्या को कम करना है। कमिटी द्वारा इन वॉचों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वॉच की लागत यात्रियों पर डाली जाएगी या सरकार/कमिटी द्वारा वहन की जाएगी—इस पर अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा। महाराष्ट्र से हर वर्ष बड़ी संख्या में हज यात्री इस पवित्र यात्रा पर निकलते हैं। इस वर्ष भी राज्य का कोटा तय किया जा चुका है। इसके साथ सुरक्षा व्यवस्था को

और मजबूत बनाने के लिए यह तकनीकी कदम उठाया गया है। अधिकारियों का मानना है कि यह प्रणाली हज प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाएगी और यात्रियों को यात्रा के दौरान एक सुरक्षित अनुभव प्रदान करेगी।

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह व्यवस्था हज संचालन को आधुनिक और सुरक्षित रूप देने में मदद करेगी। बुजुर्ग और पहली बार हज पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए यह सुविधा विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी।

इस प्रकार, आने वाली हज यात्रा में महाराष्ट्र के यात्रियों को स्मार्ट वॉच के रूप में एक नया सुरक्षा कवच मिलेगा, जो उनके धार्मिक सफर को अधिक सुरक्षित, संगठित और तनाव-मुक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

IND vs SA 2nd T20: जितेश शर्मा नॉट आउट – बेल्स लगीं और लाईट जली, फिर भी फलंदाज सुरक्षित

नई चंडीगढ़ – भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में एक बेहद रोचक और अनोखी घटना देखने को मिली। भारतीय बल्लेबाज जितेश शर्मा के साथ ऐसा हुआ कि गेंद स्टंप पर लगी, बेल्स हिली और स्टंप की लाईट भी जल गई, लेकिन उन्हें नॉट आउट घोषित किया गया।

मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज ओटनील बार्टमैन की गेंद स्टंप को छूते हुए बेल्स पर लगी और स्टंप की लाइट जली। क्रिकेट नियमों के अनुसार बेल्स पूरी तरह गिरेने तक बल्लेबाज को आउट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से जितेश शर्मा सुरक्षित रहे। यह अनोखी घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और क्रिकेट फैंस में चर्चा का



विषय बन गई। कई विशेषज्ञों ने इसे “नसीब का क्षण” बताया, क्योंकि आमतौर पर बेल्स की लाईट जलना आउट का संकेत माना जाता है, लेकिन इस मामले में निर्णय अलग निकला। जितेश शर्मा ने मैच में कुल 27 रन बनाए, जिसमें दो चौके और दो छक्के शामिल

थे। भारत ने 162 रन बनाए जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 51 रन से यह मुकाबला जीत लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया और क्रिकेट पेज पर तेजी से शेयर किया जा रहा है, और फैंस इस अद्भुत क्षण पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।



ब्रेकिंग न्यूज़ 12 दिसंबर 2025 — शीर्ष राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय अपडेट

नई दिल्ली: देश और दुनिया से आज 12 दिसंबर 2025 की प्रमुख खबरों में कई बड़े घटनाक्रम शामिल हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR वोटर सूची से एक नाम हटाने पर कड़ा चेतावनी संदेश दिया है। वहीं भारत के निर्यात में 15% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है जो नवंबर में लगभग 36 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। भारतीय रुपये का विकास डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड गिरावट के

साथ ₹90.42 का स्तर छूना आर्थिक चिंता का विषय बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व ISI प्रमुख फैज़ हमीद को 14 साल की सजा सुनाई। तिब्बत में हल्का भूकंप आया है, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई। बांग्लादेश जल्द राष्ट्रीय चुनाव की तैयारी में है और यूएस फेडरल रिज़र्व ने ब्याज दरों में कटौती की है।



नागपुर: महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन के दौरान शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सरकार और मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि “यह सरकार पूरी तरह प्रचार में डूबी है। हेलिकॉप्टर उड़ाए जा रहे हैं और बैगों में योजनाओं का सामान बांटा जा रहा है। अधिवेशन खत्म होते ही तुरंत चुनाव प्रचार शुरू होगा और लगातार चुनावों का दौर

"कोण होतास तू, काय झालास तू?—मुख्यमंत्री पांघरून खाते शुरू करें": उद्धव ठाकरे का तीखा प्रहार

चलता रहेगा। नगर परिषद के चुनाव जिस तरह से कराए गए, वैसा चुनाव महाराष्ट्र ने पहले कभी नहीं देखा।”

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दूसरे राज्यों में गुंडागर्दी, हथियारों का प्रदर्शन और पैसों का खुलेआम वितरण देखा जाता था, अब वही स्थितियाँ महाराष्ट्र में दिखाई देने लगी हैं। “हम पहले दूसरे राज्यों का उदाहरण देते थे, अब संभव है कि वे राज्य महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहे हों।”

उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे नेता एक-दूसरे पर छापे मरवा रहे हैं, भ्रष्टाचार के नए-नए वीडियो और दस्तावेज़ सामने आ रहे हैं और पैसों की गड़बड़ बरामद हो रही हैं। उन्होंने कहा, “इतने खुलासों के बावजूद मुख्यमंत्री पूरी तरह चुप बैठे हैं।”

मुख्यमंत्री को ‘पांघरून खाता’ खोलने की सलाह उद्धव ठाकरे ने कटाक्ष करते हुए कहा: “मुख्यमंत्री को एक नया विभाग शुरू करना चाहिए—पांघरून मंत्रालय। इससे बाकी मंत्री कम से कम खोलकर काम कर सकेंगे, जबकि मुख्यमंत्री खुद पांघरून ओढ़कर बैठे हैं। कौन थे और क्या बन गए—यह महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है।”

विपक्ष के नेता पद पर सवाल

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने पहले ही विधानसभा में विपक्ष के नेता पद का दावा किया है और इसके लिए भास्कर जाधव का नाम भी दिया जा चुका है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने तीखे सवाल करते हुए कहा:

“जब सरकार दो-दो उपमुख्यमंत्री जैसे गैर-संवैधानिक पद बना सकती है, तो विपक्ष के नेता की नियुक्ति करने में क्यों डर रही है? 200 से ज्यादा विधायकों के समर्थन और केंद्र की ताकत होने के बावजूद सरकार आखिर किससे घबराती है?”

उद्धव ठाकरे ने कहा कि यदि विपक्ष के नेता पद पर नियम लागू किए जा रहे हैं, तो उपमुख्यमंत्री जैसे पद भी समाप्त किए जाने चाहिए। “भाजपा के लोगों ने खुद कहा है कि केवल नंबर एक को महत्व मिलता है, नंबर दो और तीन का कोई महत्व नहीं होता। तो फिर बिना किसी अधिकार वाले मंत्री किस काम के?”

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य के प्रमुख होने के बावजूद विपक्ष के नेता पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है।

TET अनिवार्यता: सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, महाराष्ट्र का रुख और 5 दिसम्बर का शिक्षक आंदोलन

संपादकीय ... |

1 सितम्बर 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को सीधे प्रभावित करने वाला ऐतिहासिक निर्णय दिया। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए Teacher Eligibility Test (TET) उत्तीर्ण करना अब केवल नियुक्ति का मानदंड नहीं रहेगा, बल्कि सेवा में बने रहने और पदोन्नति पाने की अनिवार्य शर्त होगा। कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी कि जिन शिक्षकों की सेवा में पाँच वर्ष से अधिक समय शेष है, उन्हें अगले दो वर्षों में अनिवार्य रूप से TET पास करना होगा। यदि शिक्षक परीक्षा पास नहीं करते, तो उनकी नौकरी पर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं जिनके पास पाँच वर्ष से कम सेवा शेष है, उन्हें TET से तत्काल छूट तो है, परंतु पदोन्नति इसी पर निर्भर रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह रेखांकित किया कि शिक्षा का स्तर सुधारना राष्ट्रीय प्राथमिकता है और शिक्षक गुणवत्ता इस प्रक्रिया का केंद्रीय तत्व है। अदालत ने यह भी कहा कि TET जैसे मानकीकृत परीक्षण शिक्षक दक्षता को सुनिश्चित करने का वैध और तार्किक तरीका है। साथ ही, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में इस अनिवार्यता की लागूता के प्रश्न को अदालत ने व्यापक सुनवाई हेतु बड़ी पीठ को भेजा है, जिसका निर्णय आगे आएगा।

इस न्यायिक फैसले का व्यापक प्रभाव महाराष्ट्र में भी देखा गया। राज्य के शालेय शिक्षण विभाग ने न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए घोषित किया कि सभी शिक्षकों को 31 अगस्त 2026 तक TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। विधान परिषद में राज्य के शिक्षण मंत्री ने स्पष्ट कहा कि TET की पात्रता राष्ट्रीय ढांचे का हिस्सा है और राज्य इस मानदंड को बदल नहीं सकता। हालाँकि, सरकार ने यह जरूर संकेत दिया कि वह परीक्षा के आयोजन की आवृत्ति बढ़ाकर और अधिक प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराकर शिक्षकों की सहायता करेगी।

इसी बीच, न्यायालय के निर्णय और प्रशासनिक दबाव के बीच मौजूद शिक्षकों ने गहरी चिंता व्यक्त की। कई शिक्षक 15-20 वर्षों से सेवा में हैं और उनके लिए अचानक TET की अनिवार्यता मानसिक दबाव का कारण बनी। इन्हीं परिस्थितियों ने 5 दिसम्बर 2025 को एक बड़ा मोड़ दिया जब महाराष्ट्र के अनेक प्रमुख शिक्षक संघों—जैसे राज्य शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिति, शिक्षण संघ आदि—ने राज्यव्यापी स्कूल बंद (संप) आंदोलन का आह्वान किया। इस दिन हजारों स्कूलों में शिक्षण कार्य बाधित रहा, कई जिलों में रैलियाँ निकाली गईं तथा सरकार को पुरानी नियुक्तियों को “संरक्षण” दिए जाने की मांग प्रस्तुत की गई। शिक्षक संघों का कहना था कि TET पुरानी नियुक्तियों पर लागू करने से कई अनुभवी शिक्षकों की सेवा असुरक्षित हो जाएगी और यह अचानक परिवर्तन नीति-क्रियान्वयन की व्यावहारिक कठिनाइयों को अनदेखा करता है।

हालाँकि, यह उल्लेख आवश्यक है कि शिक्षक संगठनों की मांगें किसी भी रूप में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती नहीं देतीं। वे केवल यह सुझाव देते हैं कि सरकार—जो आदेश लागू करने की जिम्मेदार संस्था है—क्रियान्वयन प्रक्रिया को संक्रमणकालीन रूप से अधिक व्यावहारिक बनाए। उनके अनुसार, सरकार पुराने शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, अधिक संख्या में परीक्षा अवसर, अध्ययन सामग्री की उपलब्धता, तथा मार्गदर्शन शिविर जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करवाए ताकि वे नए मानकों के अनुरूप सहजता से ढल सकें। यह सभी कदम अदालत के आदेश के पूर्ण सम्मान के साथ ही लागू किए जा सकते हैं, क्योंकि ये आदेश में कोई बदलाव नहीं लाते, बल्कि उसके प्रभावी कार्यान्वयन को आसान बनाते हैं।

यह स्पष्ट है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना अनिवार्य है और न्यायालय का निर्णय इसी दिशा में उठाया गया दृढ़ कदम है। वहीं यह भी सच है कि किसी भी बड़े सुधार के दौरान उन कर्मियों के लिए संक्रमणकाल का प्रबंध करना आवश्यक होता है जो वर्षों से कार्यरत हैं। इसलिए, नीतिगत संतुलन यही होगा कि अदालत के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए शिक्षक समुदाय को आवश्यक सहूलियतें दी जाएँ, ताकि न तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य बाधित हो, और न ही सेवा में लगे हजारों शिक्षकों का मनोबल कमजोर पड़े।

Mexico Tariff on India: भारत पर टैरिफ नहीं, अपनी तरक्की पर ताला लगा रहा है मेक्सिको, चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत

● NEWS AGENCY

नई दिल्ली: अमेरिका के पड़ोसी देश मेक्सिको ने भी भारत समेत एशिया के कई देशों पर 50 फीसदी तक का टैरिफ लगा दिया है। अब यह सवाल कई लोगों के मन में है कि एक विकासशील देश, जो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ (आयात शुल्क) का शिकार है, वही टैरिफ दूसरे विकासशील देश पर क्यों लगा रहा है?

मेक्सिको की सीनेट ने उन देशों से आने वाले कई तरह के सामानों पर टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिनके साथ मेक्सिको का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (मुक्त व्यापार समझौता) नहीं है। इनमें भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। यह नया टैरिफ स्ट्रक्चर 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसके तहत कुछ सामानों पर टैरिफ 50% तक बढ़ जाएगा, जबकि ज्यादातर सामानों पर यह बढ़ोतरी करीब 35% तक सीमित रहेगी।

क्यों लगाया टैरिफ?

मेक्सिको की सरकार का कहना है कि इस कदम के पीछे अपने उद्योगों को बचाना और आर्थिक नीति को मजबूत करना है।



राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबौम की सरकार का तर्क है कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और नौकरियों को बचाने के लिए यह टैरिफ जरूरी है। उनका मानना है कि खासकर ऑटो, टेक्सटाइल, स्टील, प्लास्टिक, फुटवियर और अन्य उपभोक्ता व मध्यवर्ती सामानों के क्षेत्र में विदेशी सामानों से बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है। सरकारी अधिकारी यह भी कहते हैं कि इस टैरिफ से व्यापार में असंतुलन को ठीक किया जाएगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। इससे मेक्सिकन उत्पादकों को एशियाई देशों से आने वाले

सामानों के मुकाबले एक बेहतर मौका मिलेगा। वहीं आर्थिक रूप से देखें तो मेक्सिको अपनी आमदनी भी बढ़ाना चाहता है। विश्लेषकों का अनुमान है कि इन नए टैरिफ से साल 2026 में मेक्सिकन सरकार को करीब 3.7 अरब डॉलर का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। यह पैसा सरकार के वित्तीय घाटे को पूरा करने और बजट की कमी को दूर करने में मदद करेगा।

मेक्सिको भी घेरगा परेशानी में मेक्सिको के इस फैसले की आलोचना भी हो रही है। उनका कहना है कि इससे वैश्विक सप्लाय चेन बाधित हो

सकती है। साथ ही, निर्माताओं के लिए लागत बढ़ सकती है और दूसरे देशों के साथ व्यापारिक तनाव भी बढ़ सकता है। आलोचकों का यह भी मानना है कि मेक्सिको को कच्चे माल की लागत बढ़ानी पड़ सकती है और महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि घरेलू उत्पादकों को नए स्रोतों से सामान मंगाना पड़ेगा।

क्या ट्रंप के दबाव में उठाया कदम? रणनीतिक रूप से देखें तो मेक्सिको के

इस फैसले में एक मजबूत भू-राजनीतिक पहलू भी है। मेक्सिको का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है। यह टैरिफ बढ़ाने का फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका लैटिन अमेरिकी देशों पर चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को सीमित करने का दबाव बना रहा है।

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मेक्सिको का यह कदम अमेरिका को खुश करने के लिए है, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कनाडा एग्रीमेंट (USMCA) की अगली समीक्षा से पहले। यह अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव और अमेरिका द्वारा मेक्सिको पर टैरिफ लगाने की संभावित धमकियों को कम करने का एक तरीका भी हो सकता है।

अमेरिका पहले ही मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगा चुका है। ट्रंप बार-बार विभिन्न कारणों से मेक्सिको पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी देते रहते हैं। यह संभव है कि मेक्सिको का यह कदम ट्रंप को खुश करने के लिए हो, जो चाहते हैं कि एशियाई सामानों का अमेरिका में आना बंद हो जाए। ट्रंप का मानना है कि ये सामान मेक्सिको के रास्ते अमेरिका पहुंच रहे हैं।

Gold Silver Price: चांदी एक दिन में ₹8000 से ज्यादा महंगी, 1.96 लाख रुपये के पार पहुंची कीमत, सोने का क्या रहा हाल?

Gold Silver Price 11 December 2025: सोने और चांदी में गुरुवार को तेजी रही। एमसीएक्स पर चांदी की कीमत में 8000 रुपये से ज्यादा की तेजी आई। वहीं सोने ने भी ऊंची छलांग लगाई।

नई दिल्ली: चांदी की कीमतों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखी गई। एमसीएक्स पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी करीब 4% से ज्यादा उछलकर 1.96 लाख प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई। गुरुवार को चांदी में 8000 रुपये से ज्यादा की तेजी आई। वहीं सोने में भी 1800 रुपये से ज्यादा की तेजी देखी गई। फरवरी डिलीवरी वाले सोने का दाम 1.40% से ज्यादा उछलकर 1.31 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा हो गया। वहीं इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक राजधानी दिल्ली में भी सोने-चांदी की कीमत में तेजी आई।

इस साल चांदी की कीमतों में 113% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजहें कई हैं। लोगों की तरफ से चांदी की मांग बढ़ी है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में भी भारी निवेश हुआ है। साथ ही अमेरिका ने चांदी को एक महत्वपूर्ण खनिज (critical mineral) का दर्जा दिया है, जिससे इसकी अहमियत और बढ़ गई है। अब निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चांदी साल 2026 से पहले 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम का आंकड़ा छू पाएगी?

चांदी एक दिन में ₹8000 से ज्यादा महंगी, 1.96 लाख रुपये के पार पहुंची कीमत,



आईबीजेए का कितना रेट?

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक गुरुवार को 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 808 रुपये बढ़कर 1,28,596 रुपये हो गई। 22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,17,794 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का दाम 95,841 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 96,447 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। सोने की अपेक्षा चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। बीते 24 घंटे में चांदी का दाम 2,793 रुपये बढ़कर ऑल टाइम हाई 1,88,281 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है, जो कि पहले 1,85,488 रुपये प्रति किलो था।

क्यों आई सोने-चांदी में तेजी?

सोना और चांदी की कीमत में तेजी की वजह अमेरिका के फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) का बड़ा फैसला रहा। फेडरल रिजर्व ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इससे फेडरल फंड रेट 3.50-3.75% पर आ गया है। फेडरल रिजर्व के इस नरम रुख से बाजार में और तेजी आ गई है। पहले से ही बढ़ती औद्योगिक मांग और घटती सप्लाय से चांदी की कीमतें तेजी दिखा रही थीं। अब फेडरल रिजर्व के इस नरम रुख ने चांदी की कीमतों को और ऊपर चढ़ने का मौका दे दिया है।

प्रेगनेंट भारतीय महिलाओं को वीजा नहीं... अमेरिका ने लगाया बैन, बोला- Birth Tourism की इजाजत नहीं

NEWS AGENCY

वॉशिंगटन: भारत में अमेरिकी दूतावास ने गर्भवती भारतीय महिलाओं को वीजा देने में खास सतर्कता बरतने का ऐलान किया है। दूतावास ने कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि यात्रा का मुख्य मकसद अमेरिका में बच्चे को जन्म देना और बच्चे के लिए अमेरिकी नागरिकता हासिल करना है तो वह वीजा नहीं देंगे। दूतावास ने कहा कि इसकी इजाजत नहीं है। अमेरिका का दावा है कि हर साल बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं बच्चों को जन्म देने के लिए टूरिस्ट वीजा पर देश में प्रवेश करती हैं। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही ऐसी महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था।

अमेरिकी दूतावास ने क्या कहा

अमेरिकी दूतावास ने बयान जारी कर कहा, "अमेरिकी काउंसलर अधिकारी टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन को मना कर देंगे, अगर उन्हें लगता है कि यात्रा का मुख्य मकसद अमेरिका में बच्चे को जन्म देना और बच्चे के लिए अमेरिकी नागरिकता हासिल करना है। इसकी इजाजत नहीं है।" अमेरिका ने इसे

मुंबई: रियलिटी शो बिग के सेट मुंबई



बर्थ टूरिज्म का नाम दिया है। अमेरिका में जन्मजात नागरिकता क्या है

अमेरिका में जन्मा बच्चा, अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत स्वतः अमेरिकी नागरिक बन जाता है, चाहे उसके माता-पिता की आब्रजन स्थिति (इमिग्रेशन स्टेटस) कुछ भी हो; इसे "जन्मसिद्ध नागरिकता" (Birthright Citizenship) कहते हैं, जो माता-पिता को नागरिकता नहीं देती, पर बच्चे

को सभी नागरिक अधिकार, जैसे अमेरिकी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की क्षमता प्रदान करती है। इसके अपवाद क्या हैं

अगर बच्चा अमेरिका की जमीन पर पैदा हुआ है (कुछ अपवादों को छोड़कर), तो वह जन्म से ही अमेरिकी नागरिक है। हालांकि, विदेशी राजनयिकों के बच्चे जो आधिकारिक ड्यूटी पर अमेरिका में पैदा होते हैं, वे अमेरिकी नागरिक नहीं माने जाते हैं।

हिजाब पर फिर प्रतिबंध की तैयारी, सरकार बोली- यह उत्पीड़न का प्रतीक, जानें किस देश ने किया ऐलान

वियना

ऑस्ट्रिया की संसद के निचले सदन ने गुरुवार को 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में मुस्लिम हेडस्कार्फ पर बैन लगा दिया। हालांकि, इस बात पर अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या इस कानून को असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। दरअसल, पांच साल पहले भी इस देश में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन तब अदालत ने इस असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया था। ऑस्ट्रियाई सरकार ने इसे उत्पीड़न का प्रतीक बताया है। वहीं, मानवाधिकार समूहों और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने इसकी आलोचना की है और मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है।

संसद की सबसे छोटी पार्टी ने किया विरोध
हिजाब पर प्रतिबंध तीन सत्तारूढ़ पार्टियों के गठबंधन ने प्रस्तावित किया था। इसे धुर-दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी का भी समर्थन मिला, जो अकेली ऐसी पार्टी थी जिसने इसे स्कूल स्टाफ



पर भी लागू करने की मांग की थी। प्रस्तावित प्रतिबंध का विरोध करने वाली एकमात्र पार्टी संसद की सबसे छोटी पार्टी ग्रीन्स थी, जिसने तर्क दिया कि यह संविधान का उल्लंघन करता है।

प्रतिबंध की किसने की आलोचना | मानवाधिकार समूहों ने ऑस्ट्रियाई सरकार की इस योजना की आलोचना की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि यह "मुसलमानों के प्रति मौजूदा नस्लवादी माहौल को और बढ़ाएगा।" ऑस्ट्रिया के मुसलमानों का आधिकारिक तौर पर प्रतिनिधित्व करने वाले

संगठन ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। सरकार ने हिजाब को उत्पीड़न का प्रतीक बताया

सत्ताधारी गठबंधन की सबसे छोटी पार्टी, लिबरल नियोस के संसदीय नेता यानिक शेटी ने निचले सदन से कहा, "यह आजादी को सीमित करने के बारे में नहीं है, बल्कि 14 साल तक की लड़कियों की आजादी की रक्षा करने के बारे में है।" उन्होंने कहा, "यह (हिजाब) सिर्फ कपड़ों का एक टुकड़ा नहीं है। यह, खासकर नाबालिगों के मामले में, लड़कियों को पुरुषों की बुरी नजर

से बचाने का काम करता है। यह लड़कियों का यौन शोषण करता है।" सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कंजर्वेटिव पीपल्स पार्टी की इटीप्रेशन की जूनियर मंत्री क्लाउडिया प्लाकोल्म ने नाबालिगों के लिए हेडस्कार्फ को "उत्पीड़न का प्रतीक" बताया।

पहले भी प्रतिबंध लगा चुका है ऑस्ट्रिया

ऑस्ट्रिया की संवैधानिक अदालत ने 2020 में फैसला सुनाया था कि एक पिछला बैन, जो स्कूलों में 10 साल से कम उम्र के बच्चों पर लागू था, अवैध था क्योंकि यह मुसलमानों के साथ भेदभाव करता था और राज्य का कर्तव्य है कि वह धार्मिक रूप से तटस्थ रहे। उसने कहा कि इस सिद्धांत के खिलाफ जाने के लिए विशेष औचित्य की आवश्यकता होती है। यानिक ने कहा कि सरकार ने इस आवश्यकता को पूरा करने के प्रयास में एक अध्ययन शुरू किया है जो अभी भी जारी है, हालांकि उन्होंने इसके कंटेंट के बारे में विस्तार से नहीं बताया।

WORLD NEWS | बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव का ऐलान,

बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव का ऐलान, यूनस की किस्मत का होगा फैसला, जानें किनके बीच मुकाबला

ढाका | बांग्लादेश में 13वां संसदीय चुनाव 12 फरवरी को होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन ने गुरुवार को यह घोषणा की। अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद यह पहला चुनाव होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतदान गुरुवार 12 फरवरी 2026 को होगा। इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग हिस्सा नहीं ले पाएगी। अवामी लीग की अनुपस्थिति में मुख्य मुकाबला खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश के बीच होगा।

बांग्लादेश चुनाव का शेड्यूल जानें
चुनाव आयोग के शेड्यूल के अनुसार, नामांकन इस साल 29 दिसंबर तक दाखिल किए जाएंगे, जिनकी जांच अगले साल 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। इसके बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे, और उम्मीदवारों की अंतिम सूची 21 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव प्रचार 22 जनवरी से शुरू होगा और 10 फरवरी को सुबह 7:30 बजे तक चलेगा।



मोहम्मद यूनस ने क्या कहा? मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनस ने बुधवार को 13वें राष्ट्रीय चुनाव को जन आंदोलन के बाद एक नया बांग्लादेश बनाने का एक ऐतिहासिक अवसर बताया और इस बात पर जोर दिया कि इसे निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए। परंपरा के अनुसार, चुनाव आयोग उसी दिन बंगभवन में

राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से मिला। इससे पहले, यह मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सैयद रिफात अहमद से मिला था और रविवार को मुख्य सलाहकार प्रो मुहम्मद यूनस के साथ बातचीत की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने भाषण में मतदाताओं से बिना किसी डर के अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया।

बांग्लादेश में आचार संहिता लागू

शेड्यूल की घोषणा चुनावी प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। जन प्रतिनिधित्व आदेश, 1972 के तहत, चुनाव आयोग एक राजपत्र के माध्यम से समय-सारणी जारी करेगा, साथ ही रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों (एआरओ) की नियुक्ति भी करेगा। वे निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक कार्य संभालेंगे। आचार संहिता के अनुसार, चुनाव प्रचार मतदान से केवल तीन सप्ताह (21 दिन) पहले शुरू हो सकता है। पिछले दिनों का उपयोग उम्मीदवारी को अंतिम रूप देने, नामांकन पत्र जमा करने, जांच, नाम वापस लेने, अपील और प्रतीकों के आवंटन के लिए किया जाएगा।

सार्वजनिक स्थानों से बैनर-पोस्टर हटाने का आदेश

उम्मीदवारों को शेड्यूल की घोषणा के 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक स्थानों से पोस्टर, बैनर, होर्डिंग और बिलबोर्ड हटाने का निर्देश दिया गया है। चुनाव आयोग कैबिनेट डिवीजन को एक अर्ध-सरकारी पत्र भी भेजेगा, जिसमें सहायता मांगी जाएगी और अनुरोध किया जाएगा कि परिणाम प्रकाशित होने तक फील्ड-स्तरीय अधिकारियों का तबादला न किया जाए। शेड्यूल के साथ ही चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी।

सऊदी अरब ने 170 पाकिस्तानियों को फांसी पर लटकाया, हजारों जेल में बंद... पाकिस्तान के पत्रकार का बड़ा खुलासा, नरक जैसी जिंदगी

NEWS AGENCY |

इस्लामाबाद: सऊदी अरब में गिरफ्तार होने वाले और सजा पाने वाले विदेशी नागरिकों में पाकिस्तानी सबसे ज्यादा हैं। पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार जाहिद गिस्कोरी ने अपनी एक वीडियो रिपोर्ट में सऊदी में पाकिस्तानियों की खराब हालत का खुलासा किया है। जाहिद ने बताया है कि बीते दस साल में सऊदी अरब में आपराधिक मामलों में पाकिस्तानियों का नाम सबसे ऊपर रहा है। पाकिस्तानियों के खिलाफ सबसे ज्यादा मुकदमे हुए हैं और उनको फांसी की सजा दूसरे मुल्कों के नागरिकों से ज्यादा हुई है। जाहिद का कहना है कि सऊदी अरब में 2014 के बाद से यानी बीते 10 साल में 170 पाकिस्तानी नागरिकों को फांसी दी गई है। हत्या और दूसरे गंभीर मामलों में ये फांसी दी गई है। जाहिद ने ये आंकड़ा

सऊदी सरकार और कुछ एनजीओ के जरिए से जुटाया है। जाहिद ने इस पर चिंता जताते हुए पाकिस्तान सरकार से इस ओर ध्यान देने की अपील की है।

हजारों पाकिस्तानी जेल में बंद जाहिद ने बताया है कि बुधवार को भी एक पाकिस्तानी को सऊदी फांसी हुई है। ये दिखाता है कि सऊदी में पाकिस्तानियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। जाहिद का कहना है कि बीता साल, 2024 खासतौर से पाकिस्तानियों के लिए खराब रहा। 2024 में 21 पाकिस्तानी कैदियों को अलग-अलग मामलों में फांसी दी गई है।

जाहिद के मुताबिक, साल 2014 में सऊदी अरब में 12 पाकिस्तानियों को

फांसी दी गई थी। इसके बाद 2015 में 14 पाकिस्तानियों को, 2016 में 5 पाकिस्तानियों को, 2017 में 13 पाकिस्तानियों को 2018 में 18 पाकिस्तानियों और साल 2019 में एक पाकिस्तानी कैदी को फांसी दी गई थी। ये सजाएं अलग-अलग मामलों में दी गईं। इस साल तीन को मिली सजा सऊदी अरब में इस साल यानी 2025 में तीन पाकिस्तानियों को फांसी दी जा चुकी है। सऊदी में फिलहाल सात हजार से ज्यादा पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। इनमें से 28 को मौत की सजा हो चुकी है और कानूनी कार्यवाही चल रही है। पाकिस्तान की महिलाएं भी सऊदी की जेल में हैं। 22 पाकिस्तानी औरतें भी सऊदी के जेल में हैं। इनमें से दो महिला भी मौत की सजा पा चुकी है।





अन्ना हजारे का बड़ा ऐलान: 30 जनवरी से आमरण अनशन



प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने 30 जनवरी 2026 से महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि में लोकायुक्त कानून लागू करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन उनकी आखिरी सांस तक जारी रहेगा यदि सरकार इस कड़े भ्रष्टाचार विरोधी कानून को लागू नहीं करती। अन्ना हजारे का यह निर्णय तब आया है जब महाराष्ट्र में लोकायुक्त विधेयक दो साल पहले विधानसभा तथा विधान परिषद में पारित हो चुका है, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे वे मजबूरन अनशन की योजना बना रहे हैं। इस घोषणा से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और प्रशासन के सामने दबाव बढ़ गया है। अन्ना हजारे ने सरकार को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की चुनौती भी दी है। यह ऐलान नागपुर में चल रहे महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बीच आया है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है।

NEWS | 2029 में भी हमारा नेतृत्व उन्हीं के हाथों में होगा। पृथ्वीराज चव्हाण के बयान 2029 में नरेंद्र मोदी नहीं, क्या कोई मराठी होगा बीजेपी से पीएम कैंडिडेट? देवेंद्र फडणवीस ने दिया ये जवाब

मुंबई | महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ कर दिया कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही मैदान में उतरेगा। एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में जब फडणवीस से यह पूछा गया कि क्या वह भविष्य में प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी बन सकते हैं, तो उन्होंने इस राजनीतिक अटकल पर ये जवाब दिया। फडणवीस ने कहा कि इस पर सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी शारीरिक रूप से बेहद फिट हैं। वह 40 वर्ष के व्यक्ति जितना नहीं, बल्कि उससे भी अधिक मेहनत करते हैं। वह रोज 17 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और बैठकों में कभी थकान या जम्हाई लेते नहीं देखे जाते। जब तक वह शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हैं, तब तक उनके अलावा किसी और के बारे में सोचने का सवाल ही नहीं उठता। 2029 में



भी हमारा नेतृत्व उन्हीं के हाथों में होगा। चव्हाण के बयान के बाद छिड़ी थी ये चर्चा फडणवीस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ दिनों पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में चर्चा छेड़ दी थी। चव्हाण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वैश्विक राजनीति, विशेषकर अमेरिका में पिछले छह महीनों से चले आ रहे 'एफ्टीन फाइल्स' विवाद का उल्लेख किया था। उन्होंने दावा किया था कि यदि उन दस्तावेजों का पूरा सच सामने आता है, तो उसके प्रभाव भारत की राजनीति तक पहुंच सकते हैं। चव्हाण ने यह भी संकेत दिया था कि ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिससे भारत को एक मराठी प्रधानमंत्री मिल जाए।

फडणवीस को अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के संभावित उत्तराधिकारियों में एक बताया जाता रहा है। इसी पृष्ठभूमि में फडणवीस का यह स्पष्ट और तीखा बयान बीजेपी की आधिकारिक सोच को रेखांकित करता है, जिसमें मोदी के नेतृत्व को अब भी अपरिवर्तनीय माना जा रहा है। कॉन्क्लेव में दिए गए अपने बयान से पहले फडणवीस ने अपने तीसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरा होने पर जनता का आभार भी व्यक्त किया। छत्रपति संभाजीनगर दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने महायुती को लगातार समर्थन दिया है। हमने पिछले एक वर्ष में राज्य को विकास की पटरी पर मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य में बुनियादी ढांचे से लेकर निवेश और उद्योगों तक, कई क्षेत्रों में सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।



भूसंपादित भूमि मुआवज़ा बढ़ाने की मांग; विधायक बाबूराव कदम ने राजस्व मंत्री से की मुलाकात

नागपुर | विधानसभा के चल रहे अधिवेशन के दौरान बनचिचोली, साप्ती, तळणी, गोजेगांव, भाणेगांव, उंचेगांव और बेचिराग पांगरा ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल भूसंपादित भूमि के मुआवज़े को बढ़ाने की मांग को लेकर नागपुर पहुंचा।

उनकी जमीन सिंचित (बागायती) भूमि है। इसलिए उन्हें सिंचित भूमि के मानक के अनुसार उचित और न्यायसंगत मुआवज़ा दिया जाए।

बताया कि— “किसानों के साथ अन्याय न हो और उन्हें वास्तविक भूमि श्रेणी के अनुसार उचित मुआवज़ा प्रदान किया जाए।”

इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हदगांव-हिमायतनगर क्षेत्र के विधायक बाबूराव कदम ने सभी प्रभावित गांवों के किसानों को साथ लेकर राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से मुलाकात की।

राजस्व मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की बात गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसानों को उचित न्याय मिल सके। किसानों ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनके मांगों पर सकारात्मक और शीघ्र निर्णय लेगी।

BMC चुनाव 2025: शिंदे का मेयर पद पर स्पष्टीकरण

मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2025 को लेकर महायुति (BJP-शिंदे गुट शिवसेना-NCP) के भीतर मतभेद व अटकलों के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मुंबई का मेयर पद शिवसेना (शिंदे गुट) से ही आएगा, न कि केवल बीजेपी से, जैसा कि कुछ अटकलें हैं। शिंदे का यह बयान महायुति के भीतर संभावित खींचतान और सहयोग के सामने संकेत देता है कि गठबंधन की साझा रणनीति जारी रहेगी।



शिंदे ने यह भी कहा कि महायुति गठबंधन सभी स्थानीय निकाय चुनावों में संपर्क बनाए रखेगा, और सीट-वाटप तथा मेयर पद पर अंतिम निर्णय मुख्य नेतृत्व द्वारा संयुक्त रूप से लिया जाएगा। उन्होंने गठबंधन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि सहयोग से ही जीत सुनिश्चित होगी और मुंबई के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह बयान महायुति को एकजुट रखने की कोशिश है ताकि BMC चुनाव में सामूहिक रणनीति के साथ चुनावी लड़ाई मजबूत रूप से लड़ी जा सके। इसके साथ ही यह भी दिखाता है कि सीट-शेयरिंग और पदों के मामले में बातचीत

महायुति के नेताओं के बीच अभी भी चल रही है। इस तरह की प्रतिक्रिया से महायुति के भीतर सहयोग की दिशा स्पष्ट होती दिख रही है और यह संकेत मिलता है कि मुंबई मेयर का फैसला महायुति नेतृत्व की सहमती से ही होगा, जिससे चुनावी रणनीति अधिक सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ सके।

दृष्टिहीन क्रिकेटर कु. गंगा कदम को मिले शासकीय नौकरी; विधायक हेमंत पाटील ने मंत्री संजय शिरसाट के समक्ष रखी मांग

नागपुर | —आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दृष्टिहीन क्रिकेट खिलाड़ी तथा भारतीय दृष्टिहीन महिला क्रिकेट टीम की उपकर्णधार कु. गंगा संभाजी कदम को राज्य सरकार की ओर से शासकीय नौकरी और प्रोत्साहनात्मक मानधन प्रदान किया जाए—ऐसी मांग आज नागपुर में शुरू हुए अधिवेशन के दौरान विधायक हेमंत पाटील ने राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट के समक्ष की।



पूरे देश में मनाई गई। मराठवाड़ा की इस प्रतिभाशाली बेटी के सम्मान में हाल ही में फुटाणा गांव में 'लेकीचा सम्मान' कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ उनका नागरिक सत्कार किया गया और आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई।

हिंगोली जिले के कळमनुरी तालुके के फुटाणा गांव की निवासी गंगा कदम ने कठिन परिस्थितियों, पारिवारिक चुनौतियों और दिव्यांगत्व पर मात करते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उल्लेखनीय उपलब्धि

हासिल की है। भारतीय दृष्टिहीन महिला क्रिकेट टीम की उपकर्णधार के रूप में उन्होंने श्रीलंका में आयोजित विश्वकप प्रतियोगिता में भारत को विजेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी खुशी

कु. गंगा कदम की इस उल्लेखनीय उपलब्धि को देखते हुए विधायक हेमंत पाटील ने सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट के साथ-साथ राज्य के क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे और दिव्यांग कल्याण विभाग के समक्ष भी यह मांग रखी कि उन्हें राज्य शासन से शासकीय नौकरी और प्रोत्साहनात्मक मानधन दिया जाए।

नांदेड: शिक्षा विभाग की लापरवाही से 13 साल का वेतन बकाया

नांदेड — नगर परिषद प्राथमिक शाळा की सहशिक्षिका कादरी अफरोज सुलताना को शिक्षा विभाग की गंभीर लापरवाही के कारण 2011 से 2023 तक का वेतन बकाया रह गया। कादरी ने लातूर की इस्माईल उर्दू प्राथमिक शाळा में सेवा दी, लेकिन विभाग द्वारा समायोजन में विलंब के कारण उन्हें नियमित वेतन नहीं मिला। 2023 में उनका समायोजन नगर परिषद प्राथमिक शाळा, बिलोली में किया गया और तभी वेतन नियमित हुआ।

शिक्षकों का समायोजन तुरंत किया जाना चाहिए था, लेकिन विभाग ने इसे अनदेखा किया। उच्च न्यायालय के 2019 के आदेश के बावजूद भी यह विलंब जारी रहा, जिससे कादरी को आर्थिक कठिनाइयों और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा। राज्य अल्पसंख्याक आयोग ने 2011-2023 का थकीत वेतन तुरंत भुगतान करने और विभाग में समायोजन प्रक्रिया सुधारने की सिफारिश की है। राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी वेतन भुगतान में शीघ्रता और भविष्य में ऐसी लापरवाहियों से बचाव की मांग कर रहे हैं।



नांदेड में रेल सेवाओं के विस्तार की मांग तेज, राज्यसभा सांसद डॉ. अजित गोपछड़े ने केंद्रीय रेल मंत्री से की मुलाकात

नांदेड | नांदेड शहर और आसपास के नागरिकों की लगातार बढ़ती यात्रा आवश्यकताओं को देखते हुए रेल सेवाओं के विस्तार की मांग एक बार फिर से प्रमुखता से उठाई गई है। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. अजित गोपछड़े ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर नांदेड क्षेत्र के लिए नई रेलगाड़ियों की शुरुआत सहित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

व्यावसायिक केंद्र बताते हुए यहाँ की रेल सुविधाओं में तुरंत सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नांदेड और आसपास के जिलों के यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में नई गाड़ियों की शुरुआत, समय-सारिणी में आवश्यक सुधार तथा महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव की मंजूरी अत्यंत आवश्यक है।

मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक यात्राओं की गति मिलेगी, साथ ही यात्रियों का समय बचेगा और यात्रा अधिक सुविधाजनक व सुरक्षित बनेगी।

सांसद डॉ. गोपछड़े ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार क्षेत्रीय विकास और यात्री सुविधा को प्राथमिकता देते हुए नांदेड की इन आवश्यक मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगी।

चर्चा के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि इन मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया गया, तो नांदेड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को नई दिशा